(पाश की कविताएं)

हम लड़ेंगे साथी

हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के लिए
हम लडेंगे साथी, गुलाम इच्छाओं के लिए
हम चुनेंगे साथी, जिंदगी के टुकड़े

हथौड़ा अब भी चलता है, उदास निहाई पर
हल की लीकें, अब भी बनती हैं, चीखती धरती पर
यह काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है
सवाल के कंधों पर चढ़कर
हम लड़ेंगे साथी

कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर
बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर
हाथों पर पड़ी गांठों की कसम खाकर
हम लड़ेंगे साथी

हम लड़ेंगे तब तक
कि बीरू बकरिहा जब तक
बकरियों का पेशाब पीता है
खिले हुए सरसों के फूलों को
बीजनेवाले जब तक खुद नहीं सूंघते
कि सूजी आंखोंवाली
गांव की अध्यापिका का पति जब तक
जंग से लौट नहीं आता
जब तक पुलिस के सिपाही
अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश हैं
कि बाबू दफ़्तरों के
जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं...
हम लड़ेंगे जब तक
दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है...

जब बंदूक न हुई, तब तलवार होगी
जब तलवार न हुई, लड़ने की लगन होगी
लड़ने का ढंग न हुआ, लड़ने की जरूरत होगी
और हम लड़ेंगे साथी...

हम लड़ेंगे
कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता
हम लड़ेंगे
कि अभी तक लड़े क्यों नहीं
हम लड़ेंगे
अपनी सज़ा कबूलने के लिए
लड़ते हुए मर जानेवालों
की याद जिंदा रखने के लिए
हम लड़ेंगे साथी...

सबसे खतरनाक

मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती
गद्दारी–लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती

बैठे–बिठाए पकड़े जाना–बुरा तो है
सहमी–सी चुप में जकड़े जाना–बुरा तो है
पर सबसे ख़तरनाक नहीं होता

कपट के शोर में
सही होते हुए भी दब जाना–बुरा तो है
किसी जुगनू की लौ में पढ़ना–बुरा तो है
मुट्ठियां भीचकर बस वक्त निकाल लेना–बुरा तो है
सबसे खतरनाक नहीं होता

सबसे खतरनाक होता है
मुर्दा शांति से भर जाना
न होना तड़प का सब सहन कर जाना
घर से निकलना काम पर
और काम से लौटकर घर जाना
सबसे खतरनाक होता है
हमारे सपनों का मर जाना

सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है
आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो
आपकी निगाह में रुकी होती है।

पेज 1 का शेष

काश! ये जानते क्या है पाश!

शहीद हुए चारों पुलिसकर्मियों ने भी आतंकवादियों को उनकी मांद में जाकर ललकारा था। करनाल पुलिस एवं करनाल की जनता ने इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, इंस्पेक्टर बिजेंदर सिंह, सहायक उप निरीक्षक रघुनंदन और सिपाही नारायण सिंह की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनकी स्मृति में बना पाश पुस्तकालय आज 10 000 किताबों वाला एक बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र बन चुका है। पिछले दो दशकों में इस केन्द्र पर हिन्दी एवं पंजाबी सांस्कृतिक–साहित्यिक परिदृष्य के तमाम बड़े नाम पधार चुके हैं। पाश की बेटी एवं पत्नी भी इस स्मारक पर आ चुके हैं। पुलिस वालों का तो यहां से लगाव है ही।

पूरा करनाल शहर पाश पुस्तकालय को एक धरोहर के रूप में देखता है। यहां के बच्चे–बच्चे का लगाव इस पुस्तकालय से इसलिये भी है क्योंकि उन्हें सांस्कृतिक–साहित्यिक खुराक देने वाला ऐसा केन्द्र करनाल में तो क्या सारे प्रदेश में कहीं नहीं है। इस केन्द्र ने रंगमंच,मेला स्थल, प्रर्दशनी परिसर, साहित्यिक गोष्ठियों एवं सामाजिक विमर्शों के मंच का भी काम किया है। पुलिस की छवि अमूमन बहुत अच्छी नहीं समझी जाती। पर पाश पुस्तकालय पुलिस और जनता के बीच एक सांझी कड़ी की तरह है। इस मंच से पुलिस ने कितनी बार जनकार्यक्रम किये होंगे और जनता की वाहवाही बटोरी होगी कि जिनका कोई लेखा–जोखा ही नहीं। पुलिसकर्मियों का आम मानना है कि यदि यह स्मारक किसी गये–बीते घटिया से नेता के नाम पर होता तो आज इसके गिरने की नौबत न आई होती। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खाते में तो पूरे हरियाणा में एक मात्र शहीद हुए हैं उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जिनकी स्मृति में सारे प्रदेश में संस्थानों के नामकरण किये जा रहे हैं। स्वयं रोहतक में करोड़ों की लागत से एक स्मारक बनाया गया है, ऐन हाईवे के साथ। यदि कल इसे हाईवे चौड़ा करने के नाम पर किसी अन्य सरकार द्वारा मुनाफ़ाखोरी के लिये गिराया जाय तो कैसा लगेगा?

हरियाणा पंजाब के बौद्धिक हल्कों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसा जीवन्त स्मारक बंगाल, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, उड़िसा जैसे संस्कृतिक रूप से सजग प्रदेशों में गिराया जा सकता है? बंगाल और केरल में तो जनता सड़कों पर आकर ऐसा सोचनेवाले नेताओं का गरेबान पकड़ लेती। पर यह सांस्कृतिक रूप से संवेदनहीन राजनेताओं का हरियाणा है। गनीमत है कि सुमिता सिंह जैसों को दिल्ली का राजपाट नहीं मिला है, वरना वे राजघाट और शान्तिवन तक को भी बेच खाने से परहेज नहीं करते।

पेज 8 का शेष

नवाज शरीफ़ को जल्द चुनना पड़ेगा

समाज में दकियानूसी फ़तवों की बाढ़ आ गयी है। ले–देकर देश की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शरीफ़ को नहीं छेड़ा है क्योंकि फ़ौज और तालिबान के विरुद्ध दोनों का एजेंडा मिलता जुलता है। क्या उपरोक्त समीकरण नवाज शरीफ़ को स्थिरता दे पायेंगे? अपने लिये समर्थन जुटाने की मुहिम पर वे अमेरिका पहुंच तो गये हैं पर वहां उन्हें कई अप्रिय प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्थिक सहायता जारी रखी है और इससे शरीफ़ को अपने देशवासियों को आश्वस्त करने का मौका मिल जाता है। पर अमेरिका द्वारा चिह्नित आतंकियों के पाकिस्तानी अदालतों में चल रहे मुकदमों में कोई प्रगति न होने का जवाब दे पाना शरीफ़ के लिये भारी है। इसी प्रकार पाकिस्तान में अमेरिका द्वारा किये जा रहे ड्रोन हमलों पर रोक लगाने का कोई आश्वासन न मिलने से शरीफ़ की हालत पतली होती है।

कूटनीति के जानकारों का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में यह अनिर्णय भरा रूकाव इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अफ़गानिस्तान में जिस तरह अमेरिका फ़सा हुआ है, उसके पास ड्रोन हमले रोकने का विकल्प नहीं है। शरीफ़ को भी पता है कि कशमीर मामले में अमेरिकी मध्यस्थता तभी संभव है जब भारत इसके लिये हां कर दे हालांकि कशमीर मुद्दे पर कुछ न कुछ कहते रहना किसी भी पाकिस्तानी शासक की मजबूरी बन चुका है। शरीफ़ को भी इसे निभाना है। यह सब होते हुए भी, शरीफ़ भी जानते हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र की मजबूती के लिये उन्हें भारत से दोस्ती का हाथ बढाये रखना होगा। अन्यथा, फ़ौज या तालीबान या सुप्रीम कोर्ट, किसी न किसी की दखलंदाज़ी से उनका सूपड़ा साफ़ हो जायेगा। हो सकता है वे इस दिशा में पहल करने से पहले जनरल कयानी के सेवानिवृत्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हों, हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति से कशमीर में मध्यस्थता करने की अपील के पीछे उनकी यही मंशा हो कि इस प्रकार वे कशमीर के मसले पर अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं। बेशक इस अपील का कोई असर हो या न हो।

सभी जानते हैं कि नवाज़ शरीफ़ को पतली रस्सी पर चलने का करतब दिखाना है। यदि वे इस दौरान भारत की दोस्ती की तरफ़ चलते है तो न सिर्फ़ अपने देश का बल्कि अपना भी भला करेंगे। फ़ौज और तालिबानों से यदि उन्हें अपना पिंड छुड़ाना है तो एकमात्र विकल्प लोकतंत्र को पाकिस्तान में मजबूत करना होगा। यह भारत से अच्छे रिश्तों पर निर्भर करेगा।

ई एस आई मज़दूरों को केवल लूटना जानती है

लिहाज़ा दोनों (पति–पत्नी) ने स्थानीय विधायक एवं श्रम मंत्री शिवचरण लाल की भेंट–पूजा की। जिसके बल पर रजनी सेक्टर 8 के इस अस्पताल की सिविल सर्जन आ लगी और लगते ही मोटी डकैतियां मारने के लिये अपने चोर पति को भी यहां बैठा लिया। बैठाये भी क्यों न, नहीं बैठाये तो वह खर्चा कैसे पूरा होगा जो मन्त्री की भेंट–पूजा पर खर्च हुआ था। यदि विश्वस्त सूत्रों पर भरोसा करें तो यह खर्च 3 लाख से ऊपर का था।

चोर आर एस गुप्ता की जन्मपत्री खोलने पर पता चला कि जब यह नियमित सेवा में था तो भी हर छोटे बड़े काम के पैसे मज़दूरों से वसूलता था। वर्ष 1998–99 में एक जागरूक मज़दूर से जब इसने एक छोटे से काम के 500 रुपया मांगे तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर छापा मरवा दिया जिसमें इस चोर को रंगे हाथों पकड़ कर गिरफ़्तार कर लिया। इस मुकदमें में इसे 7 साल की कैद होती यदि छापा–टीम में तैनात ड्यूटी मैजिस्ट्रेट प्रदीप गोदारा ने अपनी गवाही न पल्टी होती।

गोदारा ने गवाही पलट कर जो पाप किया था उसी का खामियाज़ा आज यहां के मज़दूर भुगत रहे हैं। गोदारा ने जो किया सो किया मन्त्री शिवचरण भी कम दोषी नहीं है। श्रमिक हितों के लिये बना मन्त्री ही जब श्रम विरोधी हो जाय तो इसका जवाब तो उन्हें भी कभी तो देना ही पड़ेगा।

फ़िलहाल एस्कार्टस एम्प्लाइज़ यूनियन एवं हिन्द मज़दूर सभा ने इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया है और इस तरह के चोर–लुटेरे डॉक्टरों से निपटने की व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखना यह है कि ऐसे चोरों से सरकार स्वत: निपटती है या यूनियनों को ही संयुक्त रूप से डंडा–झंडा उठाना पड़ेगा?

खबर लिखते–लिखते पता चला है कि सोमबार दिनांक 28 अक्तूबर को एम एस डॉ.प्रतिभा राजवंशी ने इस मरीज़ को सर्वोदय अस्पताल के लिये रैफ़र कर दिया है। बेशक यहां का सारा खर्चा तो एक बार मरीज़ को ही वहन करना पड़ेगा लेकिन बाद में रो–पीट कर यह पैसा ई एस आई श्रमिक को लौटा देगी। लेकिन ग़रीब श्रमिक के लिये यह काम भी इतना सरल नहीं था। जब वह सर्वोदय अस्पताल पहुंचा तो वहां के डॉक्टरों ने बताया कि इस पर कम से कम 60–70 हज़ार का खर्चा आयेगा। इतनी भारी रकम का प्रबन्ध श्रमिक के पास नहीं था, लिहाजा वह अपने पिता को वापस घर ले गया।

प्लाटों की लूट में एफ़िडेविट का झूठ

हरियाणा सरकार का 'हूडा' विभाग प्लाटों की लूट का बड़ा मंच है। नेता, अफ़सर, प्रभावशाली, पैसे वाले, सभी इस लूट में शामिल रहे हैं। कोर्ट से रियायती दर पर प्लाट लो, एक–दो किश्ते देकर उसे बाज़ार भाव में बेचो और लाखों करोड़ों का मुनाफ़ा कमाओ। यह है सीधा तरीका–ए–वारदात जो ये विशिष्ट लोग अपनाते हैं। एक प्लाट बेचने के बाद वे पुन: नया एफ़िडेविट देने को स्वतंत्र होते हैं कि उनके पास कोई प्लाट नहीं है और उन्हें कोटे से दूसरा प्लाट दिया जाय। यह प्लाट भी बाज़ार में बेचा जाता है और इस तरह अगला प्लाट हथियाने की तैयारी हो जाती है। जब से 'हूडा' बना है यह धंधा चल रहा है।

अब प्रदेश भर में फ़र्जी एफ़िडेविट देकर प्लाट लेने का मामला सामने आया है। इसके फ़लस्वरूप पचासों मुकदमें दर्ज किये जा चुके हैं। हालांकि तथ्य यह है कि यदि पिछले 40 वर्षों के झूठे एफ़िडेविटों की पड़ताल की जाय तो हरियाणा में कोई–कोई ही नेता या

अफ़सर अपराधी कहलाने से बच पायेगा। मौजूदा मुकदमों की शुरूआत फ़ौजी कोटे से हुई है। फ़ौजियों की लालसा समझ में आती है क्योंकि उनके दो पुराने जनरल विज व कपूर मुम्बई के ऐसे ही मामलों में फ़से हुए हैं। कपूर को तो हरियाणा के सी एम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सहपाठी होने के नाते चार प्लाट हरियाणा में ही कोटे से दे रखे हैं। 'हूडा' विभाग स्वंय भी बड़े विल्डरों की दलाली का अड्डा ही बना हुआ है। फ़िर बेचारे एफ़िडेविट देने वालों पर गाज गिराने का क्या मतलब?